*श्री*सचदेवा बनाम; हरियाणा राज्य और अन्य (एपी चौधरी, जे.)

समक्ष: एपी चौधरी, जे.

श्री सचदेवा,-याचिकाकर्ता,
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

आपराधिक विविध. नहीं।1989 का 2436-एम
30 अप्रैल, 1990

दंड प्रक्रिया संहिता(1974 का द्वितीय)—एस.एस. 362, 482—प्रतिकूल टिप्पणियों को निर्णय से हटाना—अंतर्निहित शक्तियां—कब प्रयोग किया जा सकता है.

(2) 1990 (1) आरएसजे 34.

*आयोजित,*मामले की योग्यता के आधार पर, न्यायालयों ने तीन गुना परीक्षण लागू किया है। ये हैं (ए) क्या पक्ष न्यायालय के समक्ष हैं; (बी) क्या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उस टिप्पणी को उचित ठहराते हैं; और (सी) क्या मामले के निर्णय के लिए टिप्पणियाँ आवश्यक हैं (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नैन, एआईआर 1964 एससी 703 देखें)। उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले में लागू करने पर, मुझे लगता है कि माना जाता है कि एमआर सचदेवा उक्त पिछली कार्यवाही में एक पक्ष नहीं थे, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के मद्देनजर साक्ष्य टिप्पणियों को उचित नहीं ठहराते थे और उक्त टिप्पणियां आवश्यक नहीं थीं मामले का फैसला.¬

(पैरा 7)

धारा के तहत याचिका482, सीआर. पीसी, प्रार्थना करती है कि न्याय के हित में, उपरोक्त टिप्पणियों को उपरोक्त निर्णय से हटा दिया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील नवकिरण सिंह।

एसएस गोरीपुरिया, वकील, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए वकील डीडी गुप्ता।

प्रलय

एपी चौधरी, जे.

(1) यह आपराधिक विविध मामले में 30 सितंबर, 1988 के फैसले से कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत एक याचिका है। 1988 का नंबर 6057-एम।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक इंद्र देव गौड़ द्वारा दायर एक याचिका (सीआरएल विविध संख्या 6057-एम 1988) पर, भारतीय डाकघर की धारा 52 के तहत एफआईआर संख्या 228, दिनांक 2 अगस्त, 1987 कार्य; .1898, याचिकाकर्ता श्री एमआर सचदेवा, जो कि सीनियर पोस्टमास्टर थे, के कहने पर रद्द कर दिया गया था। एफआईआर को रद्द करने के आदेश के अंतिम पैराग्राफ में यह कहा गया था: -

> "सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और ऊपर बताए गए कारणों से, मुझे पता चला है कि वर्तमान एफआईआर गुप्त कारणों से शुरू की गई है और यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

याचिकाकर्ता 'गुप्त कारणों' शब्दों को हटाने की मांग करता है ताकि ये शब्द उसके सेवा करियर को प्रभावित न करें और इन परिस्थितियों में उसने वर्तमान याचिका दायर की है।¬

(3) ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, याचिकाकर्ता ने ऊपर उल्लिखित मुख्य आदेश में भरोसा किए गए प्रत्येक परिस्थिति को समझाने के प्रयास में सहायक दस्तावेजों के साथ बेहतर विवरण प्रस्तुत किया। उनका प्रयास यह दर्शाना है कि विपक्षी इंद्र देव गौड़ तथ्यों की समग्रता लाने में विफल रहे या कुछ तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। याचिकाकर्ता के पास उन परिस्थितियों को समझाने का कोई मौका नहीं था क्योंकि उसे इंद्र देव गौड़ द्वारा दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत मूल कार्यवाही में एक पक्ष नहीं बनाया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की अनसुनी निंदा की गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था और जो उपरोक्त टिप्पणियों को हटाने के लिए अपने आप में पर्याप्त आधार था। इंद्र देव गौड़ द्वारा एक विस्तृत जवाब दायर किया गया है जिसमें तथ्यों का खंडन किया गया है और दोहराया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ गलत इरादों के साथ पिछली एफआईआर दर्ज की गई थी।¬¬¬

(4) प्रतिवादी क्रमांक 2, इंद्र देव गौड़ के विद्वान वकील द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई है। आपत्ति यह है कि संहिता की धारा 362 के तहत एक बार किसी मामले के निपटारे के फैसले या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, उसे बदला नहीं जा सकता है या नहीं लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने के अलावा समीक्षा की गई। अजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1) का संदर्भ दिया गया था। पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने उड़ीसा राज्य बनाम राम चंदर अग्रवाल आदि (2) पर बहुत अधिक भरोसा किया। अंतिम उल्लिखित प्राधिकार में यह माना गया था कि संहिता की धारा 362 में प्रयुक्त 'नो कोर्ट' शब्द में सभी न्यायालय शामिल हैं और यह सभी निर्णयों के संबंध में लागू होता है। आगे यह माना गया कि धारा 561-ए (पुरानी संहिता के तहत) के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग न्यायालय को अपने आदेश की समीक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो विशेष रूप से धारा 369 (पुरानी संहिता) द्वारा धारा 362 के अनुरूप निषिद्ध है। वर्तमान कोड. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के संदर्भ में, उपरोक्त प्राधिकारी में यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि अंतर्निहित शक्ति संहिता द्वारा विशेष रूप से निपटाए गए किसी भी मामले से संबंधित नहीं हो सकती है, - पैरा 16 के अनुसार राम चंदर अग्रवाल के मामले में (सुप्रा)। इसलिए, तर्क यह है कि यदि उपरोक्त निर्णय से कोई भी शब्द हटा दिया गया है, तो यह निर्णय की समीक्षा करने जैसा होगा जो स्वीकार्य नहीं है।

(5) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि उच्च न्यायालय के पास न केवल संहिता की धारा 482 के तहत अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने की शक्ति है, बल्कि

न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने का कर्तव्य। विद्वान वकील ने विनोद कुमार जैन और अन्य बनाम जेपी शर्मा और अन्य (3) का हवाला दिया, जिसमें यह सवाल सीधे तौर पर उठा। मलिक शरीफ-उद-दीन. जे । जिसने पहले कुछ टिप्पणियाँ पारित की थीं, जिनके निष्कासन की मांग एक बाद की याचिका में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के पास उक्त पाठ्यक्रम को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों में आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने और समाप्त करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है।

(6) इस मामले पर लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मुद्दा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम (4) के फैसले में स्पष्ट रूप से शामिल है। शीर्ष नोट किया गया (डी) कानून को इन शब्दों में सारांशित करता है: -

> “उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा या निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को समाप्त कर सकता है यदि अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो; हालाँकि अधिकार क्षेत्र असाधारण प्रकृति का है और इसका प्रयोग

(3) 1986 (2) सीएलआर 110.
(4) एआईआर 1964 एससी 703।

एम '.ii सचदेवा *वी*हरियाणा राज्य और अन्य (ए. पी. चौधरी, जे.)

केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।¬

इसलिए प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है।

(7) मामले की योग्यता के आधार पर, न्यायालयों ने तीन परीक्षण लागू किए हैं। ये हैं: (ए) क्या पक्ष न्यायालय के समक्ष हैं; (बी) क्या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उस टिप्पणी को उचित ठहराते हैं; और (सी) क्या मामले के निर्णय के लिए टिप्पणियाँ आवश्यक हैं, - (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम, एआईआर 1964 एससी 703 के माध्यम से)। उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले में लागू करने पर, मुझे लगता है कि माना जाता है कि एमआर सचदेवा उक्त पिछली कार्यवाही में एक पक्ष नहीं थे, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के मद्देनजर साक्ष्य टिप्पणियों को उचित नहीं ठहराते थे और उक्त टिप्पणी आवश्यक नहीं थी मामले का फैसला.

(8) सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, याचिका की अनुमति दी जाती है और यह निर्देशित किया जाता है कि सीआरएल में 30 सितंबर, 1988 के आदेश से 'गुप्त कारण' शब्द हटा दिए जाएंगे। विविध. 1988 का नंबर 6057-एम।¬

पीसीजी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा

(1) 1982 सीएलआर 363 (एफबी)।
(2) एआईआर 1979 एससी 87